उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए जमीन की कमी किल्लत को देखते हुए न्यूनतम पचास एकड़ सटी हुई जमीन की शर्त हटा दी है

ट्रैक पर गिरने से महिला की मौत, पति जख्मी

शताब्दी ट्रेन से दंपति को फेंका

मुजफ्फरनगर | हमारे संवाददाता

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बुधवार को रेलगाड़ी में सुरक्षा दावों की पोल खोलती एक सनसनीखेज घटना देखने को मिली। गलती से शताब्दी एक्सप्रेस में चढ़े दंपति को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों ने धक्का दे दिया। इसमें महिला की ट्रैक पर गिरने से मौत हो गई जबकि पति घायल हो गया।

इस सिलसिले में आरपीएफ के एक एएसआई और एक कांस्टेबल के खिलाफा गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। ये दोनों दिल्ली आरपीएफ में तैनात हैं। इस घटना की चारों तरफ निंदा हो रही है। यह मामला संसद में भी गूंजा।

मुजफ्फरनगर में गांव नावला के निवासी राजेश्वर त्यागी सुबह अपनी पत्नी संतोष देवी के साथ सहारनपुर जा रहे थे। टिकट लेने के बाद राजेश्वर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने लगे।

इसी दौरान दिल्ली की ओर से शताब्दी स्टेशन पर पहुंची तो राजेश्वर पत्नी के साथ उसे एक्सप्रेस ट्रेन समझकर चढ़ने लगे। जबकि रेलगाड़ी मौजूद आरपीएफ के एएसआई रामचंद्र और कांस्टेबल सुभाष ने उन्हें ट्रेन में चढ़ने से रोका। इसी बीच ट्रेन चल दी। महिला ट्रेन में चढ़ चुकी थी, जबकि राजेश्वर चढ़ने का प्रयास करते हुए डिब्बे पर लटक गए। आरपीएफ के जवानों ने गलत ट्रेन में चढ़ने की बात कहते हुए महिला को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया।

महिला अपने पति राजेश्वर के ऊपर गिरी और दोनों नीचे आ गिरे। महिला पटरी पर जा गिरी और ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई। वहीं राजेश्वर जख्मी हो गए। पुलिस पर दुर्घटना साबित करने और केस दर्ज करने में आनाकानी करने के आरोप लगाए जा रहे हैं।

आरपीएफ का कारनामा

- गलती से ट्रेन में चढ़ गए थे दंपति, जवानों ने धक्का दिया
- पुलिस पर इसे दुर्घटना बताने और केस दर्ज करने में आनाकानी का आरोप

दो माह में राजनीतिक विकल्प देंगे रामदेव

चंडीगढ़ | भाषा

अब तक लगातार सियासत से दूर रहने का दावा करते रहे योगगुरु बाबा रामदेव ने भी भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए राजनीतिक विकल्प पेश करने का फैसला कर लिया है।

उन्होंने बुधवार को कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए यह जरूरी हो गया है कि संसद और विधानसभाओं में ईमानदार और योग्य व्यक्ति चुनकर जाएं। वह दो महीने के भीतर देश की जनता के समक्ष राजनीतिक विकल्प पेश करेंगे।

बाबा रामदेव ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'अब समय आ गया है कि राजनीति में परिवर्तन लाया जए। ऐसे लोग जनप्रतिनिधिबनें, जो वास्तव में आम लोगों के हित में काम कर सकें। आज जरूरत सामाजिक और आर्थिक अन्याय को खत्म कर देश को विकास के रास्ते पर ले जाने की है। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है, जो मौजूदा केंद्र सरकार में नहीं है।'

रामदेव ने कहा कि संसद में शक्तिशाली दल के कम से कम 300 सांसदों की जरूरत है।

बाबा रामदेव ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा सोलन में पतजंलि योगपीठ की जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश का स्वागत किया और कहा कि सभी प्रासंगिक रिकार्ड अदालत में पेश किए जायेंगे। उन्होंने कहा, यह जनता की जमीन है। दुनिया भर में ऐसे लाखों लोग हैं जो मेरे ट्रस्ट को जमीन देने के इच्छुक हैं।

बोले योगगुरू

- संसद में शक्तिशाली दल के 300 सांसदों की है जरूरत
- भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए राजनीतिक बदलाव का वक्त

जमीन पर यथास्थिति रखने के निर्देश दिए

शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को योगगुरु बाबा रामदेव की पतंजलि योग पीठ को पट्टे पर दी गई जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। सरकार ने हाल ही में इस जमीन को वापस ले लिया था। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की खंडपीठ ने बुधवार को सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि जमीन का पट्टा किस आधार पर रद्द किया गया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सरकार ने 19 फरवरी को सोलन जिले के साधूपुल में पतंजलि योगपीठ का 98 एकड़ जमीन का पट्टा रद्द कर दिया था।

जल सत्याग्रह से जागी सरकार

सीतापुर/रेउसा। शारदा नदी के कटान को रोकने के लिए दो दिन से दर्जन भर गांवों के सैकड़ों लोगों के जल सत्याग्रह से पसीजे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साढ़े तीन करोड़ की कार्ययोजना को मंजूर दे दी है। जिसके बाद तीन दिन से चल रहा जल सत्याग्रह समाप्त हो गया।

शारदा नदी के कटान की विभिषका को हर साल झेलने वाले दर्जनों गांव के निवासियों ने सोमवार से अपनी मांग को लेकर सोमवार से जल सत्याग्रह शुरू किया था। जिसके तहत सैकड़ों लोग कमर भर पानी में खड़े थे। जल सत्याग्रह के तीसरे दिन एसडीएम राजेश पांडेय ने शासन से निर्णय से अवगत कराया। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास पर शासन के आला अधिकारियों ने बैठक कर समस्या का हल निकाला था। **(हिटी)**

सीतापुर में बुधवार को मैग्सेसे विजेता संदीप पाण्डेय के नेतृत्व में शारदा नदी में जल सत्याग्रह करते कटान पीड़ित। • हिन्दुस्तान

आईना

नई दिल्ली में बुधवार को संसद भवन में इस्लामिक स्पीकर अली लारीजानी और साथ आए संसदीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करतीं लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। • प्रेट्र

बीएचयू नहीं लेगा मेडिकल की प्रवेश परीक्षा

वाराणसी। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) का चिकित्सा विज्ञान संस्थान सत्र 2013-14 में एमबीबीएस, एमडी, बीडीएस और एमडीएस पाठक्रमों में दाखिले के लिए इस बार प्रवेश परीक्षा नहीं आयोजित करेगा। सूत्रों के अनुसार संस्थान ने अपने को राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) से जोड़ लिया है। मेडिकल में दाखिले के लिए एकीकृत प्रवेश परीक्षा के सरकार के फैसले के अनुरूप यह पहल की गई है।

दुर्घटना से बची पूर्वा एक्सप्रेस, ड्राइवर घायल

फाफामऊ (इलाहाबाद)। नई दिल्ली से हावड़ा जा रही पूर्वा एक्सप्रेस थरवई के पास कनटेटर वायर में फंस गई। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी। इसमें ड्राइवर घायल हो गया।

लैपटॉप के लिए ब्योरा देने की तारीख बढ़ी

लखनऊ। यूपी में बारहवीं के छात्रों को मुफ्त लैपटॉप के लिए सरकारी, सहायताप्राप्त/मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थान अपने विद्यार्थियों का ब्यौरा 15 मार्च तक वेबपोर्टल पर उपलब्ध करा सकते हैं।

दिग्विजय सिंह की पत्नी का निधन

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पत्नी आशा देवी सिंह का बुधवार को निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं। 58 वर्षीय आशा देवी ने वसंत कुंज के एक अस्पताल में शाम को सात बजे अंतिम सांस ली। इस वक्त अस्पताल में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और परिवार के सदस्य मौजूद थे।

प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव से नहीं हुआ फायदा

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

सिविल सेवा परीक्षा (मुख्य) में हुए बदलावों के इसी बार से लागू होने के आसार हैं।

प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव 2011 में किए जा चुके हैं। हालांकि, इससे खास फायदा नहीं होने की बात भी कही जा रही है। क्योंकि, बदली परीक्षा प्रणाली के बाद निकले बैच में भी बड़े पैमाने पर विज्ञान पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों ने ही बाजी मारी थी।

दरअसल, पेशेवरों के सिविल सेवा में जाने से संसाधनों की बर्बादी होती है। आमतौर पर आईआईटी में इंजीनियरिंग या एम्स में डॉक्टरी पढ़ने वाले इसमें निकलते हैं। जबकि, इनकी पढ़ाई पर सरकार पहले ही भारी रकम खर्च कर चुकी होती है। परीक्षा के स्वरूप में बदलावों के लिए यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष अरूण एस निगवेकर की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने पहले परीक्षण किया था। फिर इसे अंतिम मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री के समक्ष रखा गया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव पीके मिश्रा ने बताया कि नए प्रारूप को कमोबेश प्रधानमंत्री की मंजूरी मिल गई है।

जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। इससे पूर्व कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मामलों के राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि यूपीएससी ने समिति की रिपोर्ट के आधार पर सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा के मौजूदा स्वरूप में कुछ बदलाव का सुझाव दिया था ताकि इसे मौजूदा समय के अनुसार अधिक प्रासंगिक बनाया जा सके।

सिविल सेवा परीक्षा एक नजर में

- सिविल सेवा परीक्षा के जरिये आईएएस, आईपीएस समेत 24 सेवाओं के लिए अधिकारियों की नियुक्ति होती है। करीब एक हजार सीटें हर साल होती हैं इसकी।
- मुख्य परीक्षा में विषयों के चार प्रश्न पत्रों की हिस्सेदारी 1200 अंकों की है। जबकि सामान्य अध्ययन के दो प्रश्न पत्रों के 600 और निबंध के 200 अंक जुड़ते हैं।
- आमतौर पर सिविल सेवा परीक्षा में टॉप करने वाले डॉक्टर या इंजीनियर होते हैं। परीक्षा में पास होने वाले 60-70 फीसदी साइंस से जुड़े डिग्रीधारी पेशेवर होते हैं।
- पिछली सिविल सेवा की टॉप परीक्षा आईएएस में निकले 158 छात्रों में से 56 इंजीनियर, 18 डाक्टर, 19 साइंटिस्ट एवं नौ प्रबंधन डिग्रीधारी थे।

आईआरसीटीसी पर 10 लाख का जुर्माना ठोंका

नई दिल्ली। दिल्ली की एक उपभोक्ता अदालत ने दो उपभोक्ताओं को अधिकत विक्रय मूल्य (एमआरपी) से अधिक कीमत पर शीतल पेय बेचने के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (आईआरसीटीसी) पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है।

नई दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच ने दो अलग-अलग मामलों पर आईआरटीसी पर पांच-पांच लाख का जुर्माना लगाया। उसने कहा कि सरकारी निगम होने के कारण आईआरसीटीसी से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। उपभोक्ता अदालत ने कहा, हमने मामले पर अनुचित एवं प्रतिबंधात्मक व्यापारिक कामकाज के रूप में विचार किया। आईआरसीटीसी से ऐसे लचर रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। दोनों शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि आईआरसीटीसी ने माजा की एक बोतल उन्हें 15 रुपये में दी, जबकि इसकी एमआरपी 12 रुपये है। **(एजेंसी)**

जलवायु परिवर्तन से हो रही हानि का 75 से 80 फीसदी मूल्य विकासशील देशों भुगतेंगे

खेती पर पड़ रही है प्रकृति व व्यवस्था की मार

मुजफ्फरपुर | अतुल कुमार सिंह

जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण का ही मुद्दा नहीं है बल्कि इससे आनेवाली पीढी के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न होनेवाली है। एक आकलन के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन से हो रहे नुकसान का 75 से 80 प्रतिशत मूल्य विकासशील देशों को चुकाना पड़ेगा। इसके लिए विकासशील देशों को हर साल 80 अरब डॉलर की जरूरत होगी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्थापन का अध्ययन करनेवाली संस्था आईडीएमसी के मुताबिक, 2010 में बाढ़ एवं सूखे की वजह से दुनिया भर में करीब 4 करोड़ महिलाओं और बच्चों को पलायन करना पड़ा है। आईडीएमसी के अनुसार, अगले 30 सालों में 16 देशों में जलवायु संकट बुरी से प्रभाव डालेगा। इनमें से 10 देश केवल एशिया के हैं। खेतिहर किसान, मजदूर, पशुपालक और मछुआरे इसके प्रभाव में आनेवाले सबसे सरल लक्ष्य हैं। विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक असर ग्रामीण और कृषि आधारित समुदायों पर पड़नेवाला है। फसलों के चक्र में परिवर्तन उनका नाश और लोगों के विस्थापन इस समस्या के अभिन्न अंग होंगे। दुनिया की आबादी में करीब 1.7 अरब लोग आज भी कृषि पर निर्भर हैं।

इसलिए जलवायु परिवर्तन की कोई भी सार्थक बातचीत कृषि की उपेक्षा कर नहीं की जा सकती। हालांकि, जलवायु परिवर्तन से होनेवाले नुकसान पर नियंत्रण के बड़े-बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बावजूद प्रकृति में बदलाव को रोका नहीं जा सका है। प्रभाव साफ हैं कि मानसून का चक्र बिगड़ रहा है। मौसम का मिजाज बदल रहा है। इसका असर दूरदराज तकग गांवों, खेत-खलिहानों तक में हो रहा है। सबसे अधिक प्रभाव तो कृषि पर पड़ रहा है, जहां परंपरागत रूप से उत्पादित होती आ रहीं बड़ी संख्या में फसलों का नामो-निशान तक मिट गया है।

इन फसलों की जगह शुद्ध रूप से बड़ी कंपनियों द्वारा निर्देशित-नियंत्रित बीजों और उनके द्वारा बताए बीजों ने ले लिया है, जिसके पैदावार और पुनरुत्पादन पर उनका ही पूरा नियंत्रण हो रहा है। कम पानी और रासायनिक खादों के बिना पैदा होने वाली कई फसलें समाप्त हो चुकी हैं और उसकी जगह नई फसलों ने ले लिया है। इनमें बड़ी मात्रा में रासायनिक खादों, कीटनाशकों, परिमार्जित बीजों और सिंचाई की जरूरत पड़ती है। इसके कारण ग्राम्य जीवन में भी बदलाव आया है। तत्काल कृषि की जरूरतों के मुताबिक हल-बैलों की जगह ट्रैक्टरों ने ले लिया है और परंपरागत अनुभवों और ज्ञान के आधार पर चली आ रही खेती की जगह अब विशेषज्ञों द्वारा निर्देशित खेती लेती जा रही है।

'बिना टीईटी बीएड वालों के लिए क्या किया'

इलाहाबाद। प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में नॉन टीईटी बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका देने संबंधी हाईकोर्ट के16 जनवरी के आदेश पर की गई कार्रवाई का ब्योरा तलब किया गया है।

एक याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस डीपी सिंह ने प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दरअसल हाईकोर्ट ने प्रभाकर सिंह की ओर से दाखिल स्पेशल अपील की सुनवाई करते हुए 16 जनवरी को सरकार को आदेश दिया था कि 50 फीसदी अंकों के साथ स्नातक और बीएड डिग्रीधारियों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। **(वसं)**